दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–18)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

GSM (M-I)-2418

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Vivek yadav

Mobile Number:

Medium (English/Hindi): Hindi

Reg. Number:

Center & Date: 525 Confrence hall

UPSC Roll No. *(If allotted)*: 7810112

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

1. संसदीय उत्तरदायित्व के स्तर को निर्धारित करने में विपक्षी दलों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये।

(150 शब्द) 10

The role of opposition parties is critical in determining the level of parliamentary accountability. Discuss.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संसदीय परंपरा मे सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका, न केवल राजनीतिक उत्तरदायित्व बढाती है, बल्कि स्वस्थ लोकतंत्र को भी जीवंत रखती है।

कानूनी पक्ष

↳ भारतीय संविधान मे विपक्ष के नेता का प्रावधान नही परंतु 1977 मे सदन प्रक्रिया अनुरूप 10% वोटशेयर हासिल करने वाली पार्टी के नेता को / अन्यथा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी।

विपक्षी दलो की भूमिका

① कार्यपालिका पर नियंत्रण

↳ प्रस्तावो के माध्यम से
- → अविश्वास प्रस्ताव
- → निंदा प्रस्ताव
- → विशेषाधिकार प्रस्ताव

↳ संकल्पो के माध्यम से।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② सत्ता पक्ष के समक्ष जरूरी मुद्दे उठाना

- प्रश्नकाल में प्रश्न पूछकर
- शून्यकाल में अपने क्षेत्र की समस्या सामने
- बजटीय मुद्दों का निष्पादन (ध्यान आकर्षण)

③ निजी बिलों को पेश करना

- गंभीर मुद्दों के संबंध में।

④ विपक्षी दलों की एकजुटता महत्व

- गठबंधन सरकारों का चलन
- क्षेत्रीय मुद्दों का हल
- संविधान के अनुरूप सरकार

चुनौतियाँ
- विपक्षी सांसदों का निलंबन
- आपसी गुटबाजी प्रतिद्वंदिता (समय कम मिलना)
- अध्यक्ष की भूमिका
- सदनों में विशेषज्ञता कमी

संसदीय समितियों में विपक्ष को पर्याप्त भूमिका दी जाए, और संसदीय परंपरा से उपाध्यक्ष का पद आवंटित किया जाना चाहिए

drishti | दृष्टि The Vision

2. महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
Discuss the role of Self-Help Groups in widening women's labour force participation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

विश्व बैंक के अनुसार → स्वयं सहायता समूह ऐसे संगठन होते है, जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि मे मिलकर कार्य करके आर्थिक गतिविधियो का संचालन करते है, और सामाजिक सशक्तिकरण बढाते है। उदा० → केरल कुटुम्बश्री

महिला श्रम बल भागीदारी बढाने में

① आर्थिक गतिविधियो को मदद
- छोटे छोटे उद्यमो को स्थापना करने मे मदद
- MSME इकाइयो को बढावा
- ऋण प्रदान करते (आपस मे सहभागिता से)

② सामाजिक प्रतिरूपो को बदलना
- महिला उद्यमियो को चारदीवारी से बाहर निकालना
- समान कार्य समान वेतन की मांग करना
- ग्रामीण महिलाओ के अधिकारो के मुद्दे उठाना

उदा० → जय अंबे SHG, राजस्थान 2 लाख तिरंगे बनाये (राष्ट्रीयता भी)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

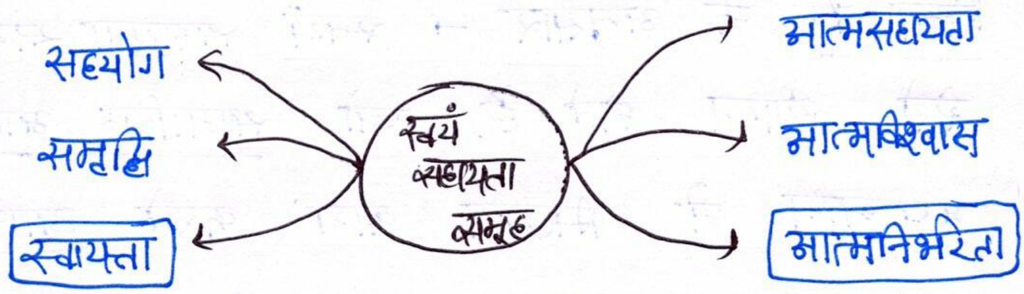

चुनौतियाँ	प्रयास
↳ वित्त की समस्या	↳ नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिकेंज प्रोग्राम
↳ जनजातीय क्षेत्रो तक पहुँच नही	↳ स्थानीय निकायो से जुडाव
↳ पर्याप्त संरक्षण नही (वित्तीय स्रोतो का)	↳ PDS सिस्टम के तहत आवंटन किया जाए (छत्तीसगढ मॉडल)
↳ जागरूकता अभाव	

ऐसे में ये स्वयं सहायता समूह श्रम बल भागीदारी और जेंडर संवेदीकरण को गति दे सकेगें।

drishti | दृष्टि The Vision

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलने से समाज के कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बल मिला है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The approach to welfare is wholesome and whole-of-society, with increasing private sector participation through Corporate Social Responsibility(CSR). Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, के तहत 5 करोड़ से अधिक शुद्ध लाभ कमाने वाली कंपनी अपनी आय का 2% सामाजिक एवं शैक्षिक उपायों के रूप में खर्च करेगी [कंपनी अधि. 2013]

CSR का मूल →

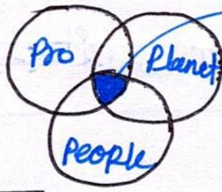

→ जनता द्वारा जनता के लिए उपाय (गांधीवादी दृष्टिकोण)

निजी क्षेत्र की भागीदारी

→ हितधारक पूंजीवाद की बात करता है
→ अर्थात ये अपने निवेशकों के साथ साथ जनता, समाज, पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होती है

→ क्रोनी कैपिटलिज्म की समाप्ति
→ पूंजीवाद को नया रूप देना, जहाँ सामाजिक एवं शैक्षिक उद्देश्यों को बढ़ावा

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

निजी क्षेत्रों के प्रयास

- स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ोत्तरी
  - उदा० उ.प्र. सरकार एवं अपोलो अस्पताल मिलकर टीबी मरीजो हेतु टेलीमेडिसिन उपाय।
- शिक्षा के क्षेत्र में
  - प्रथम जैसे NGO और ASER रिपोर्ट
  - टाटा जैसी फाउंडेशन शिक्षा मे सहयोगी।

चुनौतियाँ एवं उनका समाधान

- कंपनियो की ग्रीनवाशिंग → हरित लेखांकन को बढ़ावा
- कंपनियो की टैक्स-चोरी → विवाद से विश्वास योजना
- कंपनियो को स्वतः प्रेरित करना, कि वे सामाजिक कल्याण के लिए आगे आएँ।

4. व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के क्रम में मानसिक स्वास्थ्य, कम ध्यान दिये जाने वाला लेकिन प्रभावशाली चालक है। चर्चा कीजिये। इस संबंध में सरकार की सकारात्मक नीति क्या है? (150 शब्द) 10

Mental health is a less seen yet principally impactful driver of individual and national development. Discuss. What is the Government's positive policy momentum in this regard? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

स्वास्थ्य के पहलू मे मानसिक स्वास्थ्य सदैव अनदेखा पहलू रहा है, ऐसे मे बढती बीमारियाँ, तनाव, कुंठा, मानसिक अलगाव, डिप्रेशन, आत्महत्या आज इस ओर ध्यान खींच रहे है।

मानसिक स्वास्थ्य पर कम ध्यान → सामाजिक मुद्दा मानना कई बार परिवार अपने बच्चो की बीमारी छुपा लेते है।

- → समाज के मानदंड जैसे डिप्रेशन / तनाव को कमजोरी मानना
- → शिक्षा की पिछडी भूमिका जो मार्क्स संचालित है ऐसे मे बच्चो पर भी दबाव
- → विशेषज्ञो की कमी (वित्त आवंटन नही).
- → मानसिक रोगो को धार्मिकता और अंधविश्वास से जोडकर देखना।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रीय विकास में आवश्यक

- व्यक्ति की उत्पादकता आवश्यक होती है। वही तनाव में यह कमजोर हो जाती।
- GDP में मानवीय कमजोरी (GDP को 2 से 3% नुकसान)
- स्वस्थ नागरिक ही देश का सबसे प्रमुख धन होते हैं
- समाज में अनैतिकता और हिंसा/अलगाव की चुनौती रोकने हेतु इन पर नियंत्रण जरूरी

प्रयास

- → राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
- → टेलीमानस और मनोदर्पण पहल
- → REDS पहल जो मनोविशेषज्ञों की टीम के तहत कार्य
- → फ्री काउंसलिंग की सुविधा, विद्यालयी स्तर से
- → हेल्पलाइन नंबर (MWCD के तहत)

इन उपायों से मानसिक स्वास्थ्य के आजादी के विषय पर जनता है और स्वास्थ्य भी

drishti | दृष्टि The Vision

5. ग्रामीण भारत के शासन में सुधार हेतु शुरू की गई विभिन्न डिजिटलीकरण पहलों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the multiple digitization initiatives that have been unfolding in rural India to improve governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत की 69% आबादी ग्रामीण परिवेश मे निवास करती है, ऐसे डिजिटल इंडिया की पहल की सफलता ग्रामीण सहभागिता एवं समावेशीकरण के माध्यम से ही संभव हो सकेगी।

ग्रामीण शासन मे सुधार हेतु पहल

① ई गवर्नेंस के माध्यम से

- प्रगति पोर्टल (परियोजनाओ की निगरानी हेतु)
- PM दिशा केंद्र (योजनाओ के क्रियान्वयन केंद्र)
- PM वाणी (इंटरनेट और WIFI पहुंच)
- RTI और सिटीजन चार्टर जैसे उपकरण।

② डिजिटल इंडिया के माध्यम से

- पंचायतो को इंटरनेट से जोड़ना (भारतनेट पहल)
- दस्तावेजो की ऑनलाइन प्राप्ति (डिजीलॉकर)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

↳ भूमि मानचित्रों का डिजिटलीकरण करने हेतु (PM स्वामित्व योजना)

③ शिक्षा के माध्यम से

→ ऑनलाइन शिक्षा और edtech प्लेटफार्म
↳ मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट

जिस कारण नव किसानों का भी कृषि क्षेत्र से सीधा जुड़ाव

④ रोजगार के माध्यम से

→ मनरेगा का GIS सॉफ्टवेयर (आवंटन में पारदर्शिता)
→ CPGRAM के माध्यम से रोजगार संबंधी शिकायत दर्ज
↳ mygov.in पोर्टल, उमंग ऐप

उपरोक्त डिजिटल पहल संचालित हैं, परंतु इनका प्रभाव केवल तभी हो सकेगा, जब बेहतर क्रियान्वयन और संचालन हो सकें।

6. भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस लिखित संघीय संविधान को नम्यता (Flexibility) प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विस्तारपूर्वक समझाइये। (150 शब्द) 10

A distinctive feature of the Indian Constitution is that it seeks to impart flexibility to a written federal Constitution. Elaborate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है, इसके माध्यम से भारत को अर्द्धसंघीय संविधान की संज्ञा भी दी गई है (के. सी. व्हेयर)

नम्यता के प्रमुख उदा०

(1) संविधान का एक बडा भाग, बिना राज्यो की सहमति से ही संभव है, वही कई प्रावधानो को सामान्य बहुमत से क्रियान्वयन।

(2) आपातकाल मे संविधान का रूप परिवर्तन।

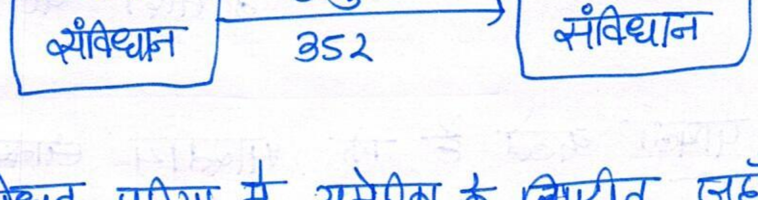

(3) संशोधन प्रक्रिया मे अमेरिका के विपरीत जहाँ 3/4 राज्यो का समर्थन आवश्यक, भारत मे केवल 1/2 राज्यो से ही।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

④ भारत मे शक्तियो के आवंटन के क्रम मे नम्यता →
उदा० तीन सूचियो का आवंटन है, परंतु आपातकाल अथवा विशिष्ट मामलो मे केंद्र को राज्य सूची के विषय पर कानूनी निर्माण अधिकार (अनु. 249)

⑤ संविधान मे शक्तियो के पृथ्यकरण को भी आसान एवं संतुलित बनाया गया है

⑥ संघीय संविधान और एकल संविधान मे यह परिवर्तन परमानेंट भी नहीं रखा, यह अपने समयानुकूल वापस (पुनित) भी हो जाता है। उदा → 352/356/360 के उत्पादन पर।

'M.V. पायली कहते है कि भारतीय संविधान का शरीर संघात्मक और आत्मा एकात्मक'
ये भारत की संघीय नम्यता की विशेषता है

7. न्यायिक कार्यों की पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता एक सुदृढ़ एवं प्रभावी विधिक प्रणाली की आधारशिला है, जिससे लोक विश्वास सुनिश्चित और न्यायिक सिद्धांत का कार्यान्वयन संपुष्ट होता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The transparency and accountability of judicial function form the cornerstone of a robust and effective legal system, ensuring public trust and upholding the principles of justice. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संविधान भारत मे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आधारशिला रखता है, जहाँ केंद्र मे उच्चतमन्यायालय राज्यो मे उच्च न्यायालय, एवं अधीनस्थ न्यायालयो का कार्यक्षेत्र होता है।

पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता → सामाजिक एवं वितरणमूलक न्याय के अनुरूप निर्णय

- → नियुक्तियो मे भाई-भतीजावाद और चयनात्मकता न हो (अंकल जज सिंड्रोम)
- → न्यायिक प्रक्रिया अन्य दो विधायिका एवं कार्यपालिका से रोक-संतुलन युक्त, एवं संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हो
- → न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे / अनु. 50
- → पूर्ण न्याय की अवधारणा साकार हो

विभिन्न न्यायिक सिद्धांतो का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित हो

① प्राकृतिक न्याय के अनुरूप

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② सभी पक्षो को सुना जाये, तत्पश्चात निर्णय

③ निर्णयो मे भेदभाव न हो

④ महिला सशक्तिकरण व जेंडर संवेदीकरण उपाय

इन उपायो के लिए प्रयास

→ PIL याचिका (न्याय कि प्रक्रिया सामान्य तीसरा पक्ष भी आ सकता)

उदा० → हुसैनारा खातून वाद (40000 कैदियो की रिहाई)

→ न्यायिक पुनर्विलोकन (कार्यपालिका – विधायिका मनमानी रोक)

→ न्यायिक समीक्षा (अपने निर्णयो की समीक्षा)

उपरोक्त उपायो के साथ यह समझना भी आवश्यक कि संविधान ने न्यायपालिका को रक्षक के तौर पर देखा है, ऐसे मे न्यायिक सक्रियतावाद कही न्यायिक अतिशयता न हो, इसलिए संयम की भूमिका निर्धारित हो।

8. राज्यों की राजनीतिक कार्यप्रणाली के संबंध में राज्यपालों के गैर-पक्षपातपूर्ण बने रहने से संबंधित संवैधानिक अवधारणा गहन जाँच के दायरे में है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The constitutional conception of state governors occupying a non-partisan position with regard to the political functioning of states has come under severe strain. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति मे अनु. 153 मे उल्लिखित और अनु. 156 के माध्यम से संचालित होती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते है, जो राज्यपाल को सलाह प्रदान करती है

चुनौतियां

1. राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियो के संदर्भ मे
   - राज्य विधायिका के बिल पर हस्ताक्षर रोकना
   - अकारण राष्ट्रपति हेतु बिल आरक्षित करना
   - पुनर्विचार के बाद भी निर्णय न लेना।

न्यायालय ने कहा → अगर पुनर्विचार के बाद कोई विधेयक पारित होकर आता है, ऐसे मे उसे राष्ट्रपति के पास विचारार्थ नही (तमिलनाडु वाद 2023)

2. सत्र/सभा को आहूत करने संबंध मे
   - दिल्ली और पंजाब मे देखा गया कि सत्र को आहूत नही।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② विशेषाधिकार के संबंध मे

→ त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति मे राजनीतिक पक्षपात की स्थिति

→ कई बार चुनी हुई सरकारो की स्वीकृता और सुस्ती अवस्था (उदा० → तमिलनाडु मे बजट पर्चाई अभाव)

संविधान क्या कहता है

→ कुछ मामलो मे राज्यपाल को विशेषाधिकार है परंतु उनका पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग सहकारी संघवाद को चोट पहुँचाता है।

क्या बेहतर उपाय

→ पुंछी आयोग (2007) संबंधी राज्यपाल की सिफारिशे

→ राज्यपाल के कार्यालय को केंद्र के एजेंट के बजाय राज्य के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका मे रहना चाहिए

→ कार्यकाल स्पष्ट हो। निश्चित हो और बेहतर समन्वय आवश्यक है

drishti | दृष्टि The Vision

9. "कारागार सुधार न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक विधिक एवं सामाजिक आवश्यकता भी है।" इस कथन के आलोक में भारत में कारागारों की स्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

"Prison reform is not just a moral imperative, but a legal and social necessity." In light of this statement, critically analyze the state of prisons in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हाल मे मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जेल मे कैदियो की स्थिति बेहद गंभीर है, जेलो मे 104% कैदियो की संख्या, महिलाओ की गंभीर समस्या व मानवाधिकार उल्लंघन देखे जा रहे है

कारागार सुधार आवश्यक क्यो?

- राज्य के कल्याणकारी स्वरूप हेतु क्योंकि अब राज्य पुलिस स्टेट नही।
- महिलाओ की स्थिति के संदर्भ मे गर्भावस्था, मासिक धर्म आदि के संबंध मे
- न्याय प्रतिकारात्मक न होकर सुधारात्मक है, इससे मे उन्हे अमानवीय परिस्थितियो के बजाय, मानवीय जरूरतो का ध्यान रखा जाए।
- बाल सुधार गर्भ मा सुधार हो।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ एवं उनके समाधान

① कैदियों की शिक्षा व स्वास्थ्य की समस्या → शिक्षा शिविर, स्वास्थ्य शिविर

② महिला कैदियों की विशिष्टता के संदर्भ में → सेनेटरी नैपकिन, पेड की उपलब्धता

③ खानपान का ध्यान

④ कैदियों की आपसी प्रतिद्वंदिता → कड़ी सुरक्षा इंतजाम

विशिष्ट प्रयास
- → मॉडल जेल अधि- 2016
- → राज्यों की विषय सूची में ऐसे में राज्य विशिष्ट प्रयास यथा - राजस्थान खुली जेल
- → कैदियों को उनके अधिकारों की जागरूकता

इन प्रयासों के साथ मुल्ला कमेटी की सिफारिशों के माध्यम से और अधिक समन्वयता।

drishti | दृष्टि The Vision

10. भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

Discuss the need for an All-India Judicial Service (AIJS) in India, highlighting key issues and challenges in its implementation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अखिल भारतीय सेवा अनु. 312 के तहत संविधान मे उल्लिखित है। राज्यसभा विशिष्ट बहुमत के माध्यम से किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा मे दर्जा दे सकती है।

AIJS → अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की आवश्यकता

→ (1) न्यायिक प्रक्रिया मे एकरूपता आ सकेगी।

→ (2) राज्यो मे न्याय सेवा चयन मे गडबडियाँ हाल मे UPPCS-J परीक्षा मे घोटाला ऐसे मे चयन प्रक्रिया पारदर्शी।

→ (3) जिला स्तर के नीचे के न्यायाधिशो के पद पर नियुक्ति हो सकेगी, जिसका लाभ महिलाओ को।

→ (4) UPSC जैसे पारदर्शी संस्थान द्वारा विशेषज्ञता को भी बढावा मिलेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

- राज्यों से विवाद बढ़ेगा।
- समवर्ती सूची में (अधीनस्थ न्यायालय) का मुद्दा
- राज्यों को अपनी शक्ति खोने का भय।
- संघवाद में अति केंद्रीयता का मुद्दा
- एकरूपता के बजाय, विविधता और स्थानीयता संघवाद को अधिक पोषित करती है

स्वर्णसिंह समिति और विधि आयोग ने AIJS की सिफारिश की है ऐसे में राज्यों से इस मुद्दे पर विचार करके एकमत सहमति लिया जा सकता है

drishti | दृष्टि The Vision

11. सराहनीय प्रयासों के बावजूद, भारत की जनजातीय जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाओं के सफल वितरण में विभिन्न चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite commendable efforts, there are several obstacles that hinder the successful delivery of healthcare services to the tribal population of India. Analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अमृत्य सेन लिखते है कि एक ओर भारतीय स्वास्थ्य ढांचा सेनफ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया की पद्धति को परिलक्षित करता है (शहरी /मेट्रो सिटीज), वही दूसरी ओर इसकी स्थिति उप सहारा अफ्रीका से मेल खाती है (ग्रामीण /जनजातीय क्षेत्रो में स्वास्थ्य ढाचाँ कमजोर)

सराहनीय प्रयास

→ प्राथमिक स्वास्थ्य की पहुँच बढाने हेतु
- → आंगनवाडी एवं आशा/ANM द्वारा जनजातीय क्षेत्रो में कुपोषण से बचाव
- → पंचायती राज से जोड़कर
  - → उपस्वास्थ्य केंद्रो का विकास
  - → वनवासियो तक स्वास्थ्य के अवसर उपलब्ध कराना

→ योजनागत प्रयास
- → सभी को स्वास्थ्य (आयुष्मान भारत मिशन) और PMJAY (कमजोर पृष्ठभूमि वालो को)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

↳ PM PVTG मिशन → विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी इलाको में सुलभ स्वास्थ्य की पहुँच।

↳ PM जनमन → जनजातियो के विकास को बढ़ावा।

प्रमुख चुनौतियाँ

(1) दूर दराज के दुर्गम क्षेत्र
- → उ०पू. के जनजातीय क्षेत्र (पहाड़ी इलाके)
- → छत्तीसगढ़, ओडिसा के घने जंगलो वाले इलाके।

(2) स्वास्थ्य शिक्षा से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है
- → जनजातियो में स्वच्छता संबंधी जानकारी कम।
- → इंटरनेट आदि का प्रसार कमजोर, ऐसे में प्रशासन की योजनाओ तक पहुँच कम।

(3) वित्त की कमी
- → बजट में कोई विशेष प्रावधान नही
- → स्वास्थ्य बजट 1.5% of GDP → इसे 2.5% of GDP करने की माँग।

drishti
दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

④ क्षेत्रीय असमानता → देश की 30% आबादी शहरो में सीमित, परंतु स्वास्थ्य से जुडे 73% अस्पताल, बेड, डाक्टर शहरो मे ही केंद्रित

⑤ टीकाकरण का अभाव

ऐसे मे कुछ निम्न प्रयास किए जा सकते है

① जनजातीय क्षेत्रो मे → टेलीमेडीसन जैसी आधुनिक सुविधाए हो
→ ई संजीवनी

② PPP मॉडल के माध्यम से पहुच सुलभ हो,
उदा- हरियाणा सरकार + मेदांता हॉस्पिटल.
(गाँवो गाँवो तक मोबाईल वैन, T.B. रोकथाम)

③ जनजातीय क्षेत्रो मे → साप्ताहिक जाँच शिविर
→ स्थानीय स्वशासन के सहयोग से

उपरोक्त के अलावा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, WHO सहयोग, और जनजातियो को मुख्य धारा मे लाने के प्रयास करना होगे।

12. विधायी अंग के रूप में संसदीय कार्यों की गणना कीजिये। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय संस्था और उसकी प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने हेतु सुधार एवं तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई अनिवार्य है? (250 शब्द) 15
Enumerate the functions of Parliament as the legislative organ. Do you agree that reforms and urgent remedial action seem imperative for making parliamentary institutions and processes effective?

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संसद भारत की विधि निर्माता संस्था है, इसके तीन भाग है → लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधायी कार्यों को सुनिश्चित करते हुए, लोगो के अनुकूल कानून निर्माण करना इसका प्राथमिक कर्तव्य है।

विधायी अंग के रूप में कार्य

① कानूनो का निर्माण
→ नये कानून का निर्माण।
→ विधि की प्रक्रिया के अनुरूप करो का आरोपण।
→ कानूनो मे संशोधन करना।

② संविधान मे संशोधन की शक्ति
→ संविधान के प्रावधानो को आवश्यकतानुरूप वैधानिक ढंग से बदलने की शक्ति।
(साधारण बहुमत एवं विशिष्ट बहुमत से)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

③ बजटीय प्रक्रिया पर नियंत्रण

└ कार्यपालिका अपने कार्यों हेतु बजट / बिल की प्राप्ति के लिए संचित निधि से निकासन पर निर्भर है वही संसद की स्वीकृति के बाद ही निकाला जा सकता

④ कार्यपालिका की उत्तरदायित्वता सुनिश्चित करना

└ विभिन्न प्रस्तावो └ बजटीय आबंटन └ चर्चा के माध्यम से

→ अंत मे कोई बिल तभी कानून निर्मित होगा, जब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

संसदीय संस्थाओ को प्रभावी बनाने हेतु

└ ① संसदीय सदस्यो मे विशेषज्ञता की कमी

→ देश मे कनाडा की तर्ज पर संसदीय बजट कार्यालय

→ संसदीय समितियो को कार्यकाल एवं विशेषाध्यायिये की सुनिश्चितता।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(2.) हाल मे देखा गया कि संसदीय कार्यों मे कमी

↳ उदा० 1956 मे संसद 120 कार्यदिवस कार्य करती, वही 2019 से औसत 60 कार्यदिवस (एक तिहाई)

↳ बिलो को पास कराने मे लोकसभा मे औसतन समय → 10 मिनिट, और राज्यसभा → 30 मिनिट

→ PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, इन आकड़ों को ठीक करने हेतु संसद सदस्यो की भूमिका अधिक बढाने, और संयुक्त / प्रवर समितियो को बिल अधिक संख्या मे भेजने की बात

अन्य उपाय
- → प्रश्नकाल (प्रश्न पूछकर)
- → शून्यकाल (कार्यपालिका के सामने बात)
- → अल्पकालिक चर्चा
- → विशेषाधिकार समिति सशक्तिकरण

उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा संसद अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है, क्योंकि शक्ति संतुलन एवं पृथक्करण लोकतंत्र हेतु आवश्यक है

drishti | दृष्टि The Vision

13. वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कम विरोधाभासी होने के साथ विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। चर्चा कीजिये। इस दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं? (250 शब्द) 15

Alternate Dispute Resolution mechanisms are less adversarial and can provide a better substitute to the conventional methods of resolving disputes. Discuss. What are the government's efforts to bring out a transformative shift towards it? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रो से तात्पर्य - जटिल न्यायिक प्रणाली से इतर, त्वरित और लचीली न्याय व्यवस्था, जो कि लोकतंत्र एवं जनता के हितो की रक्षा करें।

कानूनी आधार

→ संविधान अनु. 39 (A) → न्याय की सुलभ पहुँच हेतु राज्य का कर्तव्य

→ NALSA 1987 → लोक अदालतो के गठन संबंधी।

प्रमुख वैकल्पिक विवाद संस्थान

① लोक अदालत → ये ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रो मे बेहतर विकल्प साबित। त्वरित और सस्ती न्याय प्रक्रिया।

इसकी विशेषता यह कि → आपसी मध्यस्थता
→ विद्वेष के बजाय सहयोग

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② फास्ट ट्रैक कोर्ट

↳ 11 वे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुकूल गठित। विभिन्न कार्यों हेतु

यथा
- → चुनाव संबंधी निर्णयों हेतु
- → महिला सुरक्षा के संबंध में
- → MP, MLA कोर्ट आदि

→ न्यायालयों में लंबित मामले कम होंगे।

③ वित्तीय विवादों को निपटारण हेतु

- → वाणिज्यक संस्थानों में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
- → IBC द्वारा निजी तौर पर विवाद समाधान हेतु

④ परिवार न्यायालय

↳ परिवार न्याया. अधि 1984 के माध्यम से

↳ विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संबंधी।

⑤ अधिकरणों का गठन

↳ न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायपालिका को बोझ कम करने में सहायक

↳ प्रशासनिक अधिनियम → अनु. 323 A, 323 B

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सरकारी प्रयास

→ अधिकरणों के गठन को बढ़ावा

- राज्यों के बीच जल विवाद निपटारण (कावेरी जल विवाद)
- वाणिज्यिक मुद्दों को सुलझाने हेतु
- → महिला सुरक्षा
  → चुनावी हिंसा
  इत्यादि के संबंध में

→ सरकार द्वारा अतिरिक्त बजटीय आवंटन

→ उदा० → ग्राम न्यायालयों (मोबाइल कोर्ट स्थापना हेतु)

→ न्याय की सुलभ पहुँच हेतु और अनु. 14, अनु. 21 के तहत व्यक्तियों को उनके अधिकार दिलाने हेतु प्रयास

हालांकि ये अधिकरण और वैकल्पिक समाधान, कई बार न्यायपालिका का क्षेत्र भी प्रभावित करते है जबकि भारतीय संविधान अनु. 50 (न्यायपालिका - कार्यपालिका) पृथक्करण की बात। ऐसे मे इन्हे पूरक प्रयास के रूप मे अपनाना चाहिए

14. दिल्ली के शासन और भारत के संघीय ढाँचे पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (GNCTD) (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Critically examine the provisions of the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) (Amendment) Act, 2023 considering its potential impact on the governance of Delhi and the federal structure of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच GNCTD संशोधन अधि॰ विवाद का विषय रहा क्योंकि जहाँ राज्य सरकार का कहना है यह असंवैधानिक है, वही केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के एवं संविधान के अनुकूल बता रही है

प्रमुख प्रावधान → दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग संबंधित निर्णयों हेतु 3 सदस्यीय परिषद –

① मुख्य मंत्री ② मुख्य सचिव ③ प्रधान गृह सचिव

यह निर्णय लेंगें, और उपराज्यपाल (LG) को अपनी रिपोर्ट सौंपेगें।

इसके अलावा LG उनकी रिपोर्ट मानने हेतु बाध्य नही होगें।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

दो प्रमुख मुद्दे

→ ① दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मुखिया की शक्तियाँ कमजोर हो रही है, जबकि कुछ समय पूर्व ही (भूमि, प्रशासन, पुलिस) को छोड़कर, अन्य कार्यों मे दिल्ली सरकार को ही मुखिया माना। [माननीय सुप्रीम कोर्ट]

② दिल्ली सरकार मे मंत्रियो को कुछ विशेष मामलो मे GNCTD से सलाह की अनिवार्यता।

③ इसके साथ साथ LG से सीधे न जुड़कर, पहले 3 सदस्यीय आयोग से विभागीय राय, जो कि विधायिका मे [कार्यपालिका के बढ़ते जोर को बताता है]

ऐसे मे चुनौतियाँ

① सहकारी संघवाद कमजोर

└→ नीति आयोग की आठवी बैठक मे दिल्ली सहित 11 विपक्षी राज्य सरकारे शामिल नही।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② केंद्र-राज्य संघर्ष विकास कार्यों को बाधित कर देता है, ऐसे मे जनता की परेशानियां।

③ दिल्ली एक संघ राज्य होने के साथ, देश की राजधानी भी, ऐसे मे यह मुद्दा राष्ट्रीय अखंडता और वैश्विक नजरो मे भी रहता।

प्रयास →

→ केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार मे आपसी सहमति बनें।

→ उपराज्यपाल का हस्तक्षेप कम हो (आवश्यकता अनुरूप)

→ राष्ट्रीय राजधानी होने के अनुरूप, केंद्र सरकार का प्रभाव भी जरूरी (एकता-अखंडता) क्योंकि विदेशी दूतावास, सुप्रीमकोर्ट आदि यही।

→ वाशिंगटन DC, कैनबरा मॉडलो का अध्ययन होना चाहिए

सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशे, एवं संसदीय गतिरोध के बजाय सहयोगी संवाद एक अच्छा विकल्प होगा।

drishti | दृष्टि The Vision

15. भारतीय लोकसभा और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अध्यक्ष की भूमिका की तुलना कीजिये। चर्चा कीजिये कि ये भूमिकाएँ अपने-अपने विधायी निकायों की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करती हैं। (250 शब्द) 15

Compare and contrast the role of speaker in the Indian Lok Sabha and British House of Commons . Discuss how these roles impact the functioning of their respective legislative bodies. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय लोकसभा मे अध्यक्ष पद, संविधान के अनु. 93 के अनुरूप है, इसकी तुलना ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस से की जाती है। जिसे हम निम्न प्रकार से देख सकते है।

असमानता

भारतीय	ब्रिटिश
→ अध्यक्ष अपनी पार्टी का सदस्य बना रहता है।	→ अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग कर देता है।
→ कई बार पार्टी समर्थित गतिविधि और विपक्षी भेदभाव की घटनाएँ देखी गई।	→ यहाँ स्वस्थ परंपरा का आह्वान, जिसमे संसदीय गतिरोध को सामंजस्यता और निष्पक्षता से हल।
→ ब्रिटेन मे अध्यक्ष, आगे भी पद पर बना रहता, वही भारत मे प्रत्येक चुनाव के बाद निर्वाचन	→ ब्रिटेन मे सदा स्पीकर, सदैव स्पीकर। तो इस मामले मे भारत की प्रक्रिया अधिक स्वस्थ प्रगतिशील।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

समानताओ मे भारत एवं ब्रिटेन दोनो मे अध्यक्षीय प्रक्रियाएँ और यह पद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

① अध्यक्ष सदन का संचालन करता है, सदन से जुड़े नियम, विनियम, कानूनो का अंतिम व्याख्याकार होता है। अर्थात न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं।

② दलबदल मामलो का निपटारण → 52वें संशोधन 1985
- सदस्यो की सदस्यता के संबंध मे
- बागियो के दल छोड़ने सम्मिलन मे

③ धन विधेयक का निर्धारण → अनु. 110
- अध्यक्ष द्वारा ही निर्धारण

④ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता → अनु. 108

⑤ संसदीय समितियो के सदस्यो का चयन
- लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से ही

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

⑥ संसदीय परंपराओं का निर्वहन और स्वीकृति के बाद ही संकल्प व प्रस्तावों पर चर्चा।

⑦ संसदीय विशेषाधिकारों की रक्षा

→ व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों अधिकारों की रक्षा

कुछ चुनौतियाँ
→ दलबदल संबंधी निर्णयों में
→ विपक्षी सांसदों के निलंबन में
→ संसद में सांसदों को अपना पक्ष रखने हेतु कम समय मिलना।
→ पार्टी गतिविधियों में अधिक संलिप्तता

ऐसे में अध्यक्ष के पद की जिम्मेवारी होती है कि वह लोकतंत्र एवं संविधान के अनुरूप अपनी भूमिका निर्वहन करे, भारत में तो यह पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ वरीयता क्रम में सातवें स्थान पर आता है

16. राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने एवं केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में वित्त आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

Critically evaluate Finance Commission's crucial role in ensuring fiscal federalism and maintaining a balance between the fiscal powers of the central and state governments. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वित्त आयोग का गठन संविधान के अनु. 280 के अनुरूप, प्रति 5 वर्ष अथवा जब राष्ट्रपति उपयुक्त समझे, किया जाता है। वित्तीय संघवाद को सुनिश्चित करने मे इसकी प्रमुख भूमिका है।

वित्त आयोग की भूमिका

① राजकोषीय संघवाद मे
- केंद्रीय पूल मे दो तरह का बंटवारा करना
  - एक तो केंद्र एवं राज्य मे ऊर्ध्वाधर आवंटन
    - एक अच्छा प्रयास 14 वे वित्त आयोग से किया, जहाँ विभाज्य पूल मे राज्यों का हिस्सा 31% से बढ़कर 41% किया गया।
  - विभिन्न राज्यो मे क्षैतिज आवंटन
    - विभिन्न मानदंडो से जिसमे – गरीबी, वनपारिस्थितिकी, जनांकिकी लाभांश... जैसे कारको के माध्यम से।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(2) अन्य आवंटनो के माध्यम से संतुलन

↳ अनु. 275 के तहत अनुदान (राज्यो को)
ये राज्यो की आवश्यकतानुसार दिया जाता है

↳ नगरपालिकाओ और अन्य स्थानीय निकायो को अपनी वित्तीय स्थिति मे सुधार करने हेतु सलाह।

→ राष्ट्रपति द्वारा अन्य किसी कार्य की सलाह देने पर उसका निर्वहन करना।

विशेष बात ये कि इसकी भूमिका सलाहकारी होती है सरकार मानने हेतु बाध्य नही होती।

वित्त आयोग से जुडी कुछ चुनौतियाँ

→ करो के बंटवारे मे अधिभार एवं उपकरो को राज्यो के साथ शामिल नही किया जाता है जबकि इनकी आय 2005 मे 8% की तुलना मे 22% तक बढ़ोतरी हो चुकी।

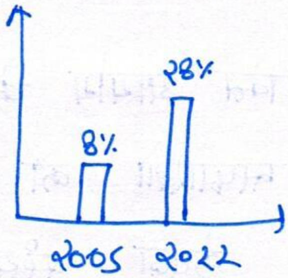

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ एक मुद्दा राज्यो के आवंटन मे, कि जहाँ दक्षिणी राज्य जनांकिकी सुधार कर रहे, वही उत्तर मे जनसंख्या ज्यादा, ऐसे मे उत्तर मे राज्यो आवंटन अधिक।

वित्त आयोग के लिए अन्य सुझाव

↳ अनुदानो के माध्यम से राज्यो को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाऐं।

↳ प्रदर्शन आधारित मानक, और निष्पादन आधारित मानदंड अपनाए जाएँ, ताकि इनसे राज्यो मे भी सहयोगी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

वित्त आयोग के कार्यालय का स्थायीकरण एवं इसकी सिफारिशो को अंशतः उत्तरदायी बनाया जाना, न केवल संसद हेतु सहायक होगा, बल्कि संघवाद को भी मजबूती मिलेगी।

drishti | दृष्टि The Vision

17. क्या भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिये अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाया है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Has India leveraged its soft power to enhance its global stature and influence? Analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वैश्विक स्थिति मे आज हार्ड पावर का स्थान साफ्ट पावर लेती जा रही है, भारत ने भी अपने विचारो, परंपराओ, सूचनाओ, शक्तिओ, संस्कृतियो के माध्यम से विश्व के सामने साफ्ट पावर का एक मानक मॉडल प्रस्तुत किया है।

① प्रवासियो के माध्यम से

- विश्व मे राजनीतिक भूमिका निभा रहे है।
- आर्थिक भूमिका मे धन प्रेषण (113 B$ सर्वाधिक)
- रोजगार मे मध्यएशिया और मध्यपूर्व मे लाखो भारतीय रिमीटेंस एवं धनापूर्ति करते
- बढ़ी मात्रा मे FDI और निवेश बढ़ाया।

प्रवासियो से राजनीतिक लाभ

- UNO मे स्थायी सुरक्षा परिषद सीट के दावेदार
- विश्व भर से भारतीयो को रिझाने का प्रयास
- भारतीयो की साफ्ट पावर को बढ़ाते है (वैश्विक केंद्र के रूप मे)

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② भारत की सकारात्मक पहलों के माध्यम से

- कोविड के समय वैक्सीन मैत्री
- श्रीलंका संकट के समय ऋण व लाइन ऑफ क्रेडिट
- अफगानिस्तान में विकास कार्य (डेलाराम हाइवे) (संसद समिति)
- ईरान में चाबहार निर्माण (वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला)
- UN में सबसे बड़ी शांति सेना (यहाँ तक कि महिलाओं द्वारा सूडान में बचाव भी)

③ विश्व में लोकतंत्र की भूमिका को आधार

- ① विविधता में एकता का प्रदर्शन
- ② सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान
- ③ पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना

④ धर्म और संस्कृति के माध्यम से

- पूर्वी और दक्षिणपूर्वी एशिया से जुड़ाव
- बुद्ध धर्म के केंद्र के रूप में

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

आंतरिक	वैश्विक
① भारत की गरीबी और बेरोजगारी।	① चीन की BRI पॉलिसी
② अवसंरचनात्मक ढाँचा कमजोर	② पाक और अन्य पड़ोसियों से संबंधों में खटास
③ धार्मिक और जातीय उन्माद	③ पड़ोसी देशों में अस्थिरता
④ क्षेत्रवाद और अन्य मुद्दे	④ वैश्विक भूपरिदृश्य (युद्धों आदि)

ऐसे में भारत अपनी आंतरिक चीजों को साधित करते हुए, योग - आयुर्वेद - नमस्ते और अन्य धार्मिक सांस्कृतिक क्रम को विश्व पटल पर लाकर 'G20' की तर्ज पर वसुधैव कुटुम्बकम का सपना पूरा कर सकता है

18. अपनी स्थापना के बाद से पिछले दो दशकों से अधिक समय में, बिम्सटेक (BIMSTEC) ने अपनी विशाल क्षमता का उपयोग करते हुए सामूहिक उन्नति की दृष्टि वाले समूह के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में एक लंबा सफर तय किया है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

In the past more than two decades since its establishment, BIMSTEC has come a long way in distinguishing itself as a group with a vision for collective advancement utilizing its vast potential. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

1997 मे स्थापित BIMSTEC समूह, दक्षिण एवं दक्षिणपूर्व एशिया के लिए ब्रिज का कार्य कर रहा है। इसे → बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय आर्थिक तकनीकी सहयोग के रूप में जानते है

बिम्सटेक की पहल

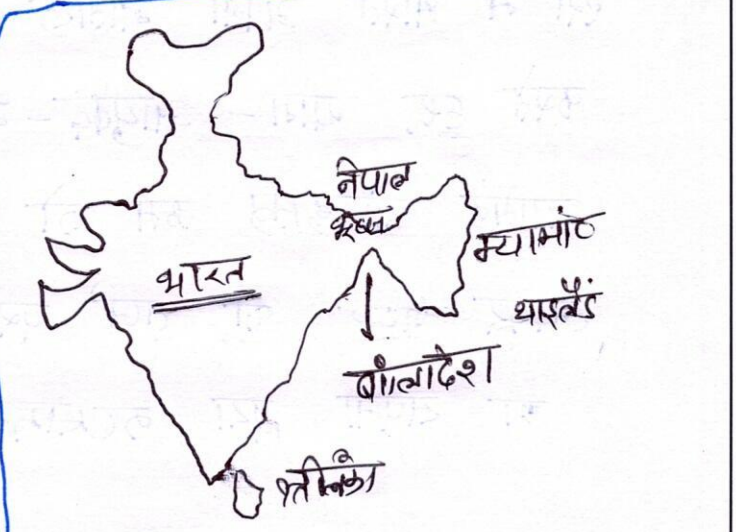

① परिवहन और कनेक्टिविटी क्षेत्र में
↳ BBIN
(बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल)
↳ IMT (इंडिया म्यांमार थाईलैंड)
↳ कलादान मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी (म्यांमार से जुड़)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② आर्थिक रूप से

- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से व्यापार को बढ़ाना
- थाईलैंड से अवसंरचनात्मक ढांचे हेतु, व्यापार।
- बांग्लादेश में भारत द्वारा परियोजनाएँ
  उदा- → मैत्री ऊर्जा संयंत्र (तापविद्युत 1.6B$)
- FTA नहीं, परंतु द्विपक्षीय व्यापार

③ सुरक्षा के रूप में

- आपरेशन सनराइज (म्यां० में अपराधियों से निपटने हेतु म्यामांर)
- बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा हेतु भारत की SAGAR (सुरक्षा एवं विकास हेतु)
- द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास

④ अन्य क्षेत्रों में सहयोग

- ITEC (भारतीय तकनीक सहयोग परिषद) → अनुदान परियोजना
- एक्ट ईस्ट और पड़ोसी प्रथम की नीति।
- जलवायु परिवर्तन रोकथाम प्रयास (ISA के माध्यम)
- आतंकवाद पर लगाम लगाने का प्रयास
- SAARC का विकल्प

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

- कोई FTA नही (व्यापार कमजोर)
- शरणार्थी का मुद्दा
- नशे, तस्करी जैसी चुनौतियाँ
- चीन का बढ़ता हस्तक्षेप (मेटीवसम न्त)
- पड़ोसी देशो मे सैन्य तख्तापलट

ऐसे मे BIMSTEC को अपने बड़े कार्यक्षेत्र के अनुरूप विकास कार्यो को गति देनी चाहिए, एवं अपने सहयोगी राज्यो की प्रतिवर्ष मीटिंग आपसी सहसंबद्धता विश्वास एवं परस्पर शांतिपूर्ण नीतियो को बढ़ावा देना चाहिए।

drishti | दृष्टि The Vision

19. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते वैश्विक ऋण संकट के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रमुख परिणामों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Examine the major outcomes of soaring global debt crisis in emerging and developing economies on international relations. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप देने के कीन्स मॉडल और पूंजीवादी मॉडल दोनो ही वित्त की आवश्यकता पर जोर देते है, ऐसे मे राष्ट्रो द्वारा लिया जाने वाले भारी ऋण कई बार चिंताजनक स्थिति भी पैदा करता है।

① विदेशी कंपनियो का बढ़ता प्रभुत्व

↳ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी कंपनिया, कई राष्ट्रो को चेकबुक डिप्लोमेसी के माध्यम से कमजोर कर रही है।

↳ कंपनियो द्वारा विश्वभर मे अपना कारोबार फैलाया जाता है, ऐसे मे परिणाम वैश्विक मंदी 1929 और 2008 के अनुरूप भी पहुंच सकते है

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(2) अंतर्राष्ट्रीय संस्थानो की भूमिका

→ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे संस्थानो द्वारा लगाई जाने वाली शर्तें।

→ ये राष्ट्रो की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते है और उन्हे बाजार अनुरूप बदलते है
उदा० - 1991 मे भारतीय अर्थव्यवस्था

(3) महाशक्तियो का प्रभुत्व

→ चीन द्वारा पड़ोसी राष्ट्रो और हिंदमहासागर मे प्रभाव

→ अमेरिका और पश्चिमी देशो द्वारा दिया गया ऋण

इन ऋण प्रक्रियाओ के गंभीर परिणाम

→ श्रीलंका संकट (हाल मे श्रीलंका की गिरती वित्तीय स्थिति)

→ बांग्लादेश और म्यांमार
  → (यहाँ भी चीन / अमेरिका जैसी शक्तियो का हाथ माना गया)

→ आर्थिक संप्रभुता के नाम पर
  → नवसाम्राज्यवाद को बढ़ावा। → राजनीतिक संप्रभुता को गिरवी रखना देता है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ राष्ट्र राज्यो के जनता के भीतर विद्वेष और अस्थिरता लाना, इससे मे अंतर्राष्ट्रीय शांति को नुकसान पहुचता है।

क्या हो बेहतर उपाय

- → सॉफ्ट लोन रणनीति
- → विश्व के समस्त राष्ट्रो द्वारा संयुक्त राष्ट्र मे बातचीत।
- → बिना शर्त ऋणो की आपूर्ति हो
- → राज्यो को आंतरिक ऋण, बचत, निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- → विश्व बैंक जैसी संस्थाओ को वरीयता दी जाए।
- → ऋण के मुद्दे पर राष्ट्रो मे आपसी समन्वय और क्षेत्रीय बैंको का उदय (BRICS) ADB आदि

गेटवर्केट मॉडल भी राज्यो की वित्तीय स्थिति सुदृढ करने मे मदद कर सकते है

20. यूरोप का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर बढ़ता ध्यान तथा भारत के साथ गहराता आर्थिक और तकनीकी सहयोग परस्पर लाभ प्रदान करता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Europe's increased focus on the Indo-Pacific and the deepening economic and technological collaboration with India offer mutual benefits. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

हिंद प्रशांत वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बना हुआ है, यहाँ न केवल एशियाई शक्तियों का प्रभुत्व बढ़ रहा है, बल्कि अमेरिका और यूरोप भी अपने पैर जमा रहे हैं

यूरोप का जुड़ाव क्यों?

- चीन की प्रभुत्ववादी नीति को रोकने में
  उदा. → AUKUS (परमाणु पनडुब्बी)
- हिंद महासागर व्यापार का विशेष केंद्र
  - उदा. स्वेज नहर, मलक्का जलसंधि
- प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय राज्यों और सैन्य अड्डों की भौगोलिक स्थिति
- यूरोप द्वारा अपने पुनर्विद्युतीकरण का उपाय

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

↳ फ्रांस जैसी शक्तियों के कुछ उपनिवेश आज भी संचालित है।

भारत के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग

→ फ्रांस का IORA और IONS के माध्यम से भारत से जुड़ाव।

→ आर्थिक गतिविधियों मे दोहरा लाभ
↳ एक तो भारत बहुत बड़ा बाजार, वही सस्ता श्रम
↳ वही भारत के लिए यूरोपीय संघ दूसरा सबसे बड़ा साझेदार

→ तकनीकी सहयोग
↳ सैन्य तकनीक मे फ्रांस से राफेल विमान (सुखोई)
↳ अंतरिक्ष तकनीकी मे सहयोग (उपग्रहो के क्षेत्र मे निगरानी)
↳ इंजीनियरिंग और साफ्टवेयर क्षेत्र मे दोनो के सहयोग।

दोनो परस्पर और क्या प्रयास कर सकते है?

① हिंद महासागर मे पॉली मेटेलिक नाड्यूल्स की खोज।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② आपसी व्यापार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख भागीदार के रूप में ब्रिटेन व EU की भूमिका हो सकती है।

③ समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती रोकना, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर साझा सहयोग।

④ आर्थिक - तकनीकी सहयोग के बल पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में एक ब्रिज स्थापित ~~करना~~ करना।

हालांकि हिंद प्रशांत क्षेत्र महाशक्तियों का रीक्रिएशन कोर्स बनकर न रह जाये, इसलिए भारत को अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, एवं अमेरिका व यूरोप के साथ बेहतर संबंधों का भी ध्यान रखना चाहिए

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)